भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

विषयः पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से संबधित सितंबर, 2023 माह का मासिक सारांश।

I. **स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस)**

i. माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री और माननीय केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 15.9.2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) पखवाड़ा 2023 का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया गया। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ग्रामीण और शहरी स्वच्छता के प्रभारी राज्य सचिवों और एसबीएम (जी) और एसबीएम (यू) के मिशन निदेशकों ने वीडियो क्रॉन्फ्रेंस में भाग लिया। डीएम/डीसी/नगर आयुक्तों/सीईओ, जिला परिषद! बीडीओ और सरपंचों ने भी वीडियो क्रॉन्फ्रेंस में भाग लिया।

ii. सचिव, डीडीडब्ल्यूएस और सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रगति में तेजी लाने के लिए 19 सितंबर, 2023 को एसीएस/प्रधान सचिव/ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी सचिव और मिशन निदेशकों (एसबीएम-जी) के साथ-साथ उनके शहरी समकक्षों के साथ एसएचएस पखवाड़ा 2023 पर एक संयुक्त वीडियो क्रॉन्फ्रेंस किया।

iii. सचिव, डीडीडब्ल्यूएस ने 23 सितंबर, 2023 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सभी एसीएस/प्रधान सचिव/ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी सचिव और मिशन निदेशकों (एसबीएम-जी) के साथ एक और समीक्षा बैठक की।

iv. सचिव, डीडीडब्ल्यूएस और सचिव, पर्यटन मंत्रालय ने 27 सितंबर, 2023 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एसीएस/प्रधान सचिव/ग्रामीण स्वच्छता/पर्यटन के प्रभारी सचिव के साथ एक संयुक्त वीडियो क्रॉन्फ्रेंस किया। वीडियो क्रॉन्फ्रेंस में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2023 और 'ट्रैवल फॉर लाइफ' अभियानों की संयुक्त रूप से समीक्षा की गई।

v. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और डीडीडब्ल्यूएस द्वारा 15 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2023 तक संयुक्त रूप से आयोजित एसएचएस पखवाड़े में भारत सरकार के 71 मंत्रालयों और विभागों ने भाग लिया, जिन्होंने स्वच्छता के नेक कार्य को अपना सहयोग देने के लिए सरकार के समग्र दृष्टिकोण का समर्थन किया, जिससे "स्वच्छता हर किसी की जिम्मेदारी" की अवधारणा को बल मिला।

vi. देश भर में प्रति दिन औसतन लगभग 6 करोड़ लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया, जिससे सूचना के अनुसार कुल भागीदारी 109 करोड़ से अधिक हो गई। 18 दिनों की अवधि में देश भर से 53 करोड़ से अधिक लोगों ने स्वच्छता के लिए श्रमदान किया,

जिसका औसत प्रति दिन लगभग 3 करोड़ लोगों की भागीदारी है। इन प्रयासों के उल्लेखनीय परिणाम दिखाई दिए - इसमें 7,611 समुद्र तटों की सफाई, 6,371 नदी तटों और जलमार्गों को पुनर्जीवित करना, 15,576 से अधिक काफी समय से जमा कचरा स्थलों को साफ करके पुनः मूल रूप प्रदान करना, 3,620 पर्यटन और प्रतिष्ठित स्थलों की स्थिति में सुधार करना और 1,23,840 से अधिक सार्वजनिक स्थानों को साफ करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, 16,000 से अधिक जल निकायों को साफ किया गया, 87,000 से अधिक संस्थागत भवनों का कायाकल्प किया गया और लगभग 66,779 कचरा स्थलों को साफ किया गया। इस 'जन आंदोलन' से राष्ट्र के लिए कई परिणाम सामने आए, जिनमें भारत के 75% से अधिक गांवों को ओडीएफ प्लस के रूप में घोषित करना और उत्तर प्रदेश, असम, त्रिपुरा और पुडुचेरी के 4 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण के तहत स्वयं को 100% ओडीएफ प्लस घोषित करना शामिल है।

vii. 'एक तारीख एक घंटा एक साथ' के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान की प्रतिक्रिया के रूप में, 1 अक्टूबर, 2023 को देश भर में आयोजित 9 लाख कार्यक्रमों में 8.76 करोड़ से अधिक लोगों (ग्रामीण क्षेत्रों में 6.86 करोड़ से अधिक सहित) ने भाग लिया।

II. जल जीवन मिशन (जेजेएम)

25.68 लाख परिवारों को कार्यशील पारिवारिक नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए, जिससे कुल संख्या बढ़कर 13.15 करोड़ हो गई। माह के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 8,191 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

सचिव, डीडीडब्ल्यूएस ने जेजेएम की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए 15 सितंबर, 2023 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक वीडियो क्रॉन्फ्रेंस बैठक की।

सचिव, डीडीडब्ल्यूएस, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय और सचिव, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने 20 सितंबर, 2023 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ जल जीवन मिशन-कौशल विकास पहल 'नल जल मित्र' कार्यक्रम की शुरूआत के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस संयुक्त रूप से वीडियो क्रॉन्फ्रेंस बैठक की अध्यक्षता की।

III. स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण - चरण - II

माह के दौरान 3,74,808 व्यैक्तिक पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) और 925 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी) का निर्माण किया गया है। माह के दौरान 6,126 गांवों को ठोस कचरा प्रबंधन के अंतर्गत कवर किए जाने और 14,486 गांवों को तरल कचरा प्रबंधन के अंतर्गत कवर किए जाने की सूचना मिली है।

14,426 गांवों ने स्वयं को ओडीएफ प्लस घोषित किया है, जिससे 5,91,758 बसे हुए गांवों में से कुल संख्या 4,48,740 हो गई है। यह देश के 75% से अधिक वे गांव हैं, जिन्होंने ओडीएफ प्लस गांव का दर्जा प्राप्त किया है, जहां खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) की स्थिति बनी हुई है और ठोस या तरल कचरा प्रबंधन व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। माह के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 704 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

माह के दौरान उत्तर प्रदेश, असम, त्रिपुरा और पुडुचेरी के 4 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने स्वयं को 100% ओडीएफ प्लस घोषित किया है, जिससे कुल संख्या 16 हो गई है।

सचिव, डीडीडब्ल्यूएस और मुख्य सचिव, गुजरात ने 6 सितंबर, 2023 को गांधीनगर, गुजरात में एसबीएम-जी और जेजेएम के कार्यान्वयन के संबंध में एक समीक्षा बैठक की सह-अध्यक्षता की, जिसमें सभी संबंधित प्रशासनिक सचिवों ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया और कलेक्टर तथा अन्य जिला अधिकारी वीडियो क्रॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए।

*****